(3) जब भी खामियां ध्यान में आती हैं खान-पान प्रबन्धकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है ।

भारतीय पोत परिवहन निगम को हुआ घाटा

*147. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पोत परिवहन निगम में सरकार का कुल पूंजी निवेश कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय पोत परिवहन निगम पिछले अनेक वर्षों से लगातार घाटा उठा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो निगम को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है, और क्या सरकार ने घाटे को नियंत्रित करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सरकार ने भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में अब तक 261.23 करोड़ रु. की कुल शेयर पूंजी विनियोजित की है।

(ख) जी, नहीं । भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड 1984–85 से लगातार लाभ अर्जित कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब

*148. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक ऐसी परियोजना की बढ़ी हुई लागत कितनी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि संबद्ध विभागों/मंत्रालयों ने लागत में हुई वृद्धि के कारण इन कोयला परियोजनाओं का विरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्तमान में प्रत्येक 20 करोड़ तथा इससे ऊपर की लागत की क्रियान्वयन अधीन 54 कोयला खनन परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और 17 परियोजनाएं पूरा होने के मामले में कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं।

(ग) कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(घ) और (ङ) संशोधित लागत अनुमानों पर अन्तर-मंत्रालयीय समूह में विचार-विमर्श किया जाता है और सार्वजनिक निवेश बोर्ड में प्रयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है सरकार को संशोधित लागत अनुमानों की स्वीकृति संबंधी सिफारिश प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वृद्धि के कारणों की समीक्षा तथा उन पर विचार-विमर्श किया जाता है ।